स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

प्रभाग
DIVISION

दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LTD.
(A Govt. of India Enterprise)

STC/BS&P/BS/10082/2017-18/STEX

November 16, 2018

Manager-Listing Compliance Department National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra – Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400051 Scrip Code : STCINDIA - EQ	Manager – Listing Compliance Department BSE Limited 1st Floor, P.J. Towers, Dalal Street Mumbai – 400001 Scrip Code : 512531

Sub: Press release of Unaudited Financial Results (Reviewed) for Quarter and Half Year ended on September 30, 2018

Dear Sir/Madam,

Please find attached herewith the Press release of Unaudited Financial Results (Reviewed) for Quarter and Half Year ended on September 30, 2018.

It is requested to same may kindly be taken on record.

Thanking you,

Yours sincerely,
For State Trading Corporation of India Limited

(Deepak C S)
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As above

जनसत्ता हिन्दी 15.11.2018

दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

(CI No. L74899 DL1956 GO1002674)

जवाहर व्यापार भवन, टालस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली–110 001 दूरभाष: 011–23313177 फैक्स: 011–23701123/23701191

30 सितंबर, 2018 को समाप्त तिमाही एवं 6 महीनों के पृथक वित्तीय परिणामों की विवरणिका

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं	विवरण	30.09.2018 को समाप्त तिमाही	30.09.2017 को समाप्त तिमाही	30.09.2018 को समाप्त छमाही	30.09.2017 को समाप्त छमाही	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
		(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
1	प्रचालनों से कुल आय	2,836.65	1,751.37	6,570.50	6,550.31	10,865.71
2	अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर पूर्व, अपवाद और/या असाधारण मदों)	(12.82)	(1.03)	(10.67)	9.00	3.02
3	अवधि के लिए कर पूर्व निवल लाभ/(हानि) (अपवाद और/या असाधारण मदों के पश्चात्)	(12.68)	9.51	(10.97)	23.36	32.25
4	अवधि के लिए कर पश्चात् निवल लाभ/(हानि) (अपवाद और/या असाधारण मदों के पश्चात्)	(13.33)	7.76	(11.87)	20.39	37.52
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर पश्चात्) और अन्य व्यापक आय (कर पश्चात्) सहित)	(13.33)	7.76	(11.87)	20.45	40.67
6	इक्विटी शेयर पूंजी	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
7	अन्य इक्विटी, पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व को छोड़कर			(25.65)	(34.00)	(13.79)
8	अर्जन प्रति शेयर (प्रत्येक 10/– रुपए का) (जारी और बाधित प्रचालनों के लिए) (वार्षिक नहीं)					
	(क) मूल (रुपए में)	(2.22)	1.29	(1.98)	3.40	6.25
	(ख) डायलूटेड (रुपए में)	(2.22)	1.29	(1.98)	3.40	6.25

नोट:

1) इन वित्तीय परिणामों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के साथ पठित इसके तहत जारी संगत नियमों और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के तहत उल्लिखित भारतीय लेखा मानक 34 'भारतीय वित्तीय रिपोर्टिंग (इंड एएस–34) में निर्धारित मान्य और परिभाषन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है।

2) 30 सितंबर, 2018 को समाप्त तिमाही और अर्धवार्षिक के वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई और निदेशक मंडल द्वारा 13 नवंबर, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में इन्हें अनुमोदित किया गया।

3) कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सेबी (सूचीबद्धता बाध्यता और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अनुसार सीमित समीक्षा की है।

4) कंपनी ने मैसर्स ग्लोबल स्टील होल्डिंग लिमिटेड और मैसर्स ग्लोबल स्टील फिलीपींस इंक (दोनों कंपनियां भारत के बाहर पंजीकृत हैं) से 318.35 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 1470 करोड़ रुपये के बराबर) के व्यापार प्राप्यों के साथ उस पर 13.50% ब्याज और अन्य प्रभारों (अन्य सहयोगी कंपनियों को छोड़कर) की वसूली के लिए दिनांक 16 नवंबर 2011 को एक समझौता करार और 17 मई 2012 को एक और निपटान समझौता करार (एफएसए) किया है। तथापि, एफएसए पर हस्ताक्षर करने के बाद कंपनी को रु 640.70 करोड़ प्राप्त हुए हैं।

रुपए 2156.49 करोड़ (रुपये 264.67 करोड़ की आकस्मिक संपत्ति को छोड़कर) के बकाया शेष हेतु मामला भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है। आगे, जीएसएचएल के एक लेनदार ने आइज्ल ऑफ मैन, यूके की अदालत में एक परिसमापन याचिका दायर की है। एसटीसी ने भी जीएसएचएल से शेष राशि की वसूली के लिए आइज्ल ऑफ मैन, यूके की अदालत में अपना दावा दायर किया है। साथ ही यह मामला भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के अंतिम चरण में है, हालांकि, ब्याज के भुगतान के संबंध में पार्टी ने आपत्ति उठाई है। उपर्युक्त के मद्देनजर, ऋण को अच्छा माना गया है और 30 सितंबर 2018 को समाप्त छमाही के लिए 139.78 करोड़ रुपये के उस पर अर्जित ब्याज को आय के रूप में माना गया है।

5) एल एंड डीओ ने पत्र संख्या 3/4(14)/68/एल–1 दिनांक 13.03.1975 के तहत जनपथ, नई दिल्ली में एसटीसी को 2.599 एकड़ भूमि का प्लॉट आबंटित किया और कार्यालय भवन यथा जवाहर व्यापार भवन के निर्माण हेतु पट्टे के लिए दिनांक 05.12.1975 को एक करार किया। कंपनी ने अपने दिनांक 09 जनवरी, 2018 को अपने पत्र के तहत अनुरोध किया गया था कि एसटीसी शाश्वत पट्टा करने की इच्छुक है। इसके अलावा यह भी अनुरोध किया गया था कि एल एंड डीओ हमें (i) सरकारी दरों के गैर भुगतान के विवरण (ii) अनधिकृत निर्माण के विवरण और (iii) अन्य उल्लंघन, यदि कोई हों, के विवरण सूचित करें।

तथापि, पट्टा विलेख की विभिन्न शर्तों के गैर–अनुपालन के लिए अपने दिनांक 26 मार्च 2018 के पत्र सं एलएंडडीओ/एलएस2ए/9225/133 के तहत रुपये 132.83 करोड़ की मांग की है। एलएंडडीओ ने आगे कहा है कि पट्टा विलेख का निष्पादन संपूर्ण भुगतान और मास्टर प्लॉन के तहत अनुमेय किए अनुसार परिसर का उपयोग करने की शर्त पर होगा। तथापि, एसटीसी ने मांग का विरोध किया है और एलएंडडीओ द्वारा की गई मांग परीक्षण के अधीन है। उक्त मांग की बाबत देयता उपलब्ध नहीं कराई गयी है क्योंकि पट्टे हेतु करार के गैर अनुपालन और राशि का पता लगाया जाना अभी शेष है।

6) व्यापार प्राप्यों, जहाँ विभिन्न पार्टियों द्वारा एसटीसी को समय पर भुगतान में चूक की है, में भारी रकम के रुक जाने के कारण एसटीसी अस्थायी वित्तीय संकट का सामना कर रही है। बकाया राशि की वसूली के लिए ग्राहकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई है। एसटीसी द्वारा सामना की जा रही मौजूदा आर्थिक संकट ढांचागत कमी के कारण नहीं है, लेकिन कुछ लेनदेनों के कारण समस्या है जिसे हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। बैंक उधार की बाबत मूलधन और ब्याज का भुगतान न करने के कारण नवंबर 2017, बैंकों ने एसटीसी के खाते को एनपीए रिपोर्ट किया है। कंपनी ने मौजूदा ऋण के पुनर्गठन और अतिरिक्त ऋण बढ़ाने के लिए वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया है। इसलिए, कंपनी ने कंपनी के प्रचालनों को व्यवहार्य और टिकाऊ बनाने के उद्देश्य से कार्यशील पूंजी ऋण के पुनर्गठन के लिए अपने ऋणदाता बैंकों को संकल्प योजना प्रस्तुत की है। ऋणदाता बैंकों ने पुनर्निर्माण योजना को अंतिम रूप देने के लिए संयुक्त ऋणदाता फोरम का गठन किया है। नीचे उल्लिखित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, ऐसा मानना है कि हम एक सतत कंपनी के रूप में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की स्थिति में होंगे:

I. वाणिज्य मंत्रालय ने 03.05.2018 को रुपए 500 करोड़ की राशि के लिए सुविधा पत्र (लेटर ऑफ कंफर्ट) जारी किया है। इसके अलावा, ऋणदाता बैंकों के आग्रह पर, मौजूदा के साथ–साथ प्रस्तावित ऋणों के लिए सरकारी गारंटी हेतु प्रशासनिक मंत्रालय से अनुरोध किया गया है। वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के पर्याप्त समर्थन ने एक सतत कंपनी के रूप में हमारे विश्वास को पुनः स्थापित किया है।

II. आगामी वर्षों में विभिन्न सहयोगियों से पर्याप्त राशि वसूल किए जाने की उम्मीद है।

III. कंपनी ने वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान 9200 करोड़ रुपये का कारोबार हासिल करने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।

IV. कंपनी ने आर्थिक स्थिति/लाभप्रदता में सुधार करने के लिए विभिन्न लागत कटौती उपाय किए हैं, जैसे कि अव्यवहार्य शाखाओं को बंद करना, उच्च व्यापार मार्जिन प्रदान करने वाली वस्तुओं में व्यापार करना और कर्मचारियों को वीआरएस देना आदि।

कंपनी की क्षमता, व्यापार योजनाओं और भावी दृष्टिकोण जैसा कि आकलन किया गया है, को ध्यान में रखते हुए कंपनी अपनी वित्तीय स्थिति को हल करने के लिए कुछ व्यावहारिक समाधान पर पहुँचने हेतु पूर्णतया आश्वस्त है।

7) कंपनी ने भारत सरकार की ओर से वर्ष 2008–09 के दौरान यूरिया का आयात किया था। कंपनी के निर्देशों का अनुपालन न करने के कारण, कंपनी ने आपूर्तिकर्ताओं के रुपए 33.04 करोड़ के पीबीजी को शेक दिया। आपूर्तिकर्ता ने मध्यस्थता के लिए मामला उठाया किया और 9.59 मिलियन अमरीकी डॉलर (लगभग 69.87 करोड़ रुपये के बराबर) की राशि और रुपए 5.22 करोड़ की अन्य लागत का मध्यस्थता निर्णय आपूर्तिकर्ता के पक्ष में दिया गया। मध्यस्थता निर्णय के अनुसार, कंपनी ऐसी देयता के परिसमापन की तारीख तक 12% प्रति वर्ष (अन्य लागत को छोड़कर) की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इसके बाद, कंपनी ने 33.04 करोड़ रुपये दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष जमा किया और दिल्ली उच्च न्यायालय में और फिर उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की। कंपनी उच्च न्यायालय के साथ–साथ उच्चतम न्यायालय में मुकदमा हार गई। चूंकि, एसटीसी द्वारा उक्त लेनदेन डीओएफ, भारत सरकार की ओर से किया गया था, एसटीसी ने डीओएफ के साथ दावा दर्ज कराया है। साथ ही एसटीसी को पैसे जारी करने के लिए मामला वाणिज्य विभाग द्वारा डीओएफ के साथ उठाया गया है। कंपनी को आशा थी कि न्यायालय आदेश की बाबत देय राशि डीओएफ से वसूली योग्य है, इसलिए इसका एसटीसी के वित्तीय परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

8) एसटीसी में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना मुख्य प्रबंधक स्तर तक, पेशेवरों को छोड़कर, 18.06.2018 से 17.07.2018 तक शुरू की गई थी। प्रथम चरण में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पहले 80 कर्मचारियों को कवर करते हुए पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर थी। कुल 101 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 06 आवेदनों को खारिज कर दिया गया था, 07 आवेदन वापस ले लिए गए थे। शेष 88 आवेदनों में से 80 कर्मचारियों के आवेदन स्वीकार कर लिये गये थे और उनकी देनदारियाँ चुकता कर दी गई हैं।

9) लेखांकन समझदारी के मामले के रूप में, 30.09.2018 को समाप्त तिमाही के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्य नहीं किया गया है।

10) पिछली अवधि के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक हो, मौजूदा अवधि के साथ तुलनीय बनाने के लिए पुनः व्यवस्थित/पुनर्गठित किया गया है।

11) उपर्युक्त विवरण सेबी (सूचीबद्धता बाध्यता और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में दर्ज किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत फार्मेट का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण फार्मेट स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों (www.nseindia.com, www.bseindia.com) तथा कंपनी की वेबसाइट (www.stclimited.co.in) पर उपलब्ध हैं।

(राजीव चोपड़ा)
निदेशक (वित्तपोषण), सीएमडी के अतिरिक्त प्रभार सहित
डीआईएन –06466326

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक: 13.11.2018

निदेशक मंडल के आदेश से
एस.के. सिंघल
महाप्रबंधक–वित्त एवं मुख्य वित्त अधिकारी

FINANCIAL EXPRESS 15/11/2018

THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Govt. of India Enterprise)
(CIN: L74899DL1956GOI002674)
Jawahar Vyapar Bhawan, Tolstoy Marg, New Delhi-110 001; Tel.: 011-23313177 Fax: 011-23701123/23701191

Statement of Standalone Financial Results for the Quarter and Six Months ended Sept 30, 2018

(Rs. crore)

Sl. No.	PARTICULARS	Quarter Ended 30.09.2018	Quarter Ended 30.09.2017	Half Year Ended 30.09.2018	Half Year Ended 30.09.2017	Year Ended 31.03.2018
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total income from operations	2,836.65	1,751.37	6,570.50	6,550.31	10,865.71
2	Net Profit /(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or Extraordinary items)	(12.82)	(1.03)	(10.67)	9.00	3.02
3	Net Profit /(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(12.88)	9.51	(10.97)	23.36	32.25
4	Net Profit /(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(13.33)	7.76	(11.87)	20.39	37.52
5	Total comprehensive income for the period [comprising Profit/ (Loss) for the period (after Tax) and other comprehensive income (after tax)	(13.33)	7.76	(11.87)	20.45	40.67
6	Equity Share Capital	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
7	Other Equity excluding Revaluation Reserves			(25.65)	(34.00)	(13.79)
8	Earning per share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)					
	(not Annualized) :					
	(a) Basic (in Rupees)	(2.22)	1.29	(1.98)	3.40	6.25
	(b) Diluted (in Rupees)	(2.22)	1.29	(1.98)	3.40	6.25

Notes:

1) These Financial results have been prepared in accordance with recognition and measurement principles laid down in the Indian Accounting Standards 34 'Indian Financial Reporting (Ind AS-34) prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India.

2) The financial results for the Quarter and Half Year Ended on 30th September, 2018 were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in its meeting held on 13th November, 2018.

3) Limited Review as per Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 (as amended) has been carried out by the statutory Auditor of the Company.

4) Company has entered into a Conciliation Agreement dated 15th November 2011 and a Further Settlement Agreement (FSA) dated 17th May 2012 for the recovery of trade receivables of USD 318.35 million (equivalent to Rs. 1470 crore approx.) including interest @ 13.50 % thereon & other charges (excluding other sister concerns) from M/s Global steel Holding Ltd and M/s Global steel Philippines Inc.(both companies are registered outside India). However, company has received Rs. 640.70 crore since signing of FSA.
For balance outstanding of Rs. 2156.49 crore (excluding Contingent Assets of Rs. 264.67 crore), the matter is pending with Hon'ble Supreme court of India. Further, one of the creditors of GSHL has filed a liquidation petition in the Isle of man, UK. STC has also filed its claim in the court of Isle of Man, UK for recovery of balance amount from GSHL. Simultaneously the case is at an advance stage of hearing with the Supreme Court of India though the party has raised the objection regarding payment of interest, the same has not been accepted by STC. In view of the above, the debt has been considered good and interest accrued amounting to Rs. 139.78 crore for the half year ended 30th September 2018 thereon is recognized as income.

5) L&DO allotted a plot of Land measuring 2.599 acres on Janpath, New Delhi to STC vide letter no.3/4(14)/68/L-1 dated 13.03.1975 and agreement for lease dated 05.12.1975 for the construction of office building viz. Jawahar Vyapar Bhawan. Company had requested L&DO vide its letter dated 09th January, 2018 that STC intends to enter into perpetual leass. Further it was also requested that L&DO may inform us the (i) Details of Non payment of Govt. dues (ii) details of unauthrized construction and (iii) the breaches, if any.
However, L&DO has raised a demand vide its letter No. L&DO/LS2A/9225/133 dated 26th March 2018 for amounting to Rs. 132.83 crore for noncompliance of various conditions of the Lease Deed. L&DO had further stated that the execution of lease deed shall be subject to complete payment & putting to use of premises as permissible under Master plan. However, STC has disputed the demand and the demand raised by L& DO is under examination. Liability for the said demand has not been provided for as the non compliance of agreement for lease and amount is yet to be ascertained."

6) STC is facing temporary financial crunch due to blockage of huge amount in trade receivable where various parties have defaulted in making timely payment to STC. Legal actions have also been taken against customers for recovery of outstanding dues. The source of current liquidity crunch faced by STC is not structural deficiency but the problem on account of some transactions which we are trying to resolve. Due to non-payment of principal and interest on bank borrowings w.e.f. November 2017, the banks reported STC's account as NPA. The company has appointed financial advisor for restructuring of existing loans and for raising additional loans. Therefore, the Company has submitted resolution plan to its lender banks for restructuring of working capital loans with the objective to make the operations of the company viable and sustainable. The lender banks have formed Joint Lender Forum to finalize the reconstruction plan. In view of below mentioned points, it is believed that we shall be in a position to confidently sail as a going concern:
   I. Ministry of Commerce has issued a Letter of Comfort dated 03.05.2018 for an amount of Rs. 500 crore. Further, at the insistence of Lender banks, a request has been made to Administrative Ministry for issuance of Govt. guarantee for the existing as well as proposed borrowings. The adequate support of Ministry of Commerce, Govt. of India, re-establishes our faith as a going concern entity.
   II. Substantial amount is expected to be recovered from various associates in the coming years.
   III. The company has signed MOU with Ministry of Commerce and Industry for turnover of Rs. 9200 crore to be achieved during the F.Y. 2018-19.
   IV. The company has undertaken various cost reduction measures to improve the liquidity/profitability such as closure of unviable branches, undertaking trade in those commodities fetching higher trade margins & VRS to employees etc. Considering the strength of the company, business plans and future outlook as assessed, the company is quite confident to reach at some workable solution to resolve financial position of the company.

7) The Company had imported urea on behalf of Govt. of India during the year 2008-09. Due to non-observance of Company's instructions, the Company invoked the PBG of the supplier for Rs. 33.04 crore. The supplier referred the matter to arbitration and the arbitral award was pronounced in favour of supplier amounting to USD 9.59 million (equivalent to Rs. 69.87 crore approx.) and other cost Rs. 5.22 crore. As per Arbitral Award, the Company is liable to pay interest @12% p.a. (excluding other cost) till the date of liquidation of such liability. Thereafter, the company deposited Rs. 33.04 crore with the Delhi High Court and filed an appeal in High Court of Delhi and then in Supreme Court. Company has lost the cases in the High Court as well as Supreme Court. Since, the said transaction was undertaken by STC on behalf of DOF, Govt. of India, STC has lodged the claim with DOF. Simultaneously the matter has been taken up by the Deptt. of Commerce with the DOF for release of money to STC. The company expected that the amount payable against Court order is recoverable from DOF hence it will have no impact on the financial results of STC.

8) Voluntary retirement scheme was introduced starting from 18.06.2018 to 17.07.2018 up to level of Chief Manager excluding professionals. The Voluntary Retirement scheme in the first phase was to cover maximum 80 employees on first come first serve basis. Total 101 applications were received out of which 06 applications were rejected, 07 applications were withdrawn. Application of 80 employees out of balance 88 applications was accepted and their dues have been settled.

9) As a matter of accounting prudence, Deferred Tax Assets for the quarter ended 30.09.2018 have not been recognized.

10) Figures of the previous period have been regrouped/ rearranged to make them comparable with those of the current period wherever necessary.

11) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites (www.nseindia.com, www.bseindia.com) of the stock Exchange(s) and Co.'s website (www.stclimited.co.in).

By order of the Board of Directors

(Rajiv Chopra)
Director (Marketing) with additional charge of CMD
DIN-06466326

Place: New Delhi
Date: 13.11.2018

(S K Singhal)
GM-F & CFO